UPSC संपादकीय लेख विश्लेषण 29 जुलाई 2021

संपादकीय लेख 1: एक निर्णय, जिसे सही भावना से लिया जाना चाहिए

टॉपिक: सामान्य अध्ययन पेपर 2 (न्यायपालिका)

संदर्भ:

- संविधान के अस्तित्व में आने के 71 वर्षों में संविधान संशोधन के केवल 104 केस हुए हैं।
- इसके अतिरिक्त, न्यायालय द्वारा एक संवैधानिक संशोधन को रद्द करना एक बहुत ही दुर्लभ घटना है, जो पिछले सप्ताह से पहले केवल सात बार हुई है।
- 20 जुलाई, 2021 को भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह के केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित हालिया फैसले में, 97वें संविधान संशोधन को सीमित तरीके से खारिज कर दिया गया था।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO)
Access to All Structured Courses & Test Series
ENROL NOW

पृष्ठभूमि

- 15 फरवरी, 2012 को 97वां संविधान संशोधन लागू किया गया था और इसने सहकारी समितियों के कानूनी शासन में कई बदलाव लाए थे।
- इसमें अनुच्छेद 19(1)(c) के अंतर्गत संघ के संरक्षित रूपों में "सहकारी समितियां" शामिल हैं, इस प्रकार सहकारी समिति के गठन को नागरिकों का मौलिक अधिकार बना दिया गया है।
- संशोधन ने संविधान में भाग IXB को भी शामिल किया था, जिसने उन शर्तों को निर्धारित किया था, जिनके द्वारा सहकारी समितियां शासित होंगी।
- अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया प्रदान करता है।
- इसके अनुसार, संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन में सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का दो-तिहाई बहुमत आवश्यक होता है।
- इसके अतिरिक्त, संविधान के कुछ अनुच्छेद और अध्याय हैं, जिन्हें केवल एक विशेष प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जिसमें संशोधन को आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा भी अनुसमर्थित करना होगा।
- हाल के मामले में, इस अतिरिक्त आवश्यकता का उल्लंघन हुआ है जिसके कारण 97वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी।
- 92वां संशोधन जिसमें कहा गया है कि सहकारी क्षेत्र को राज्य स्तर पर नियंत्रित किया जाना चाहिए, न कि केंद्र या संघ स्तर पर नियंत्रित किया जाना चाहिए, यह भारत सरकार अधिनियम, 1919 पर आधारित है, जिसने सहकारी समितियों को प्रांतीय सूची में रखा है। जिसके कारण सहकारी समितियों को संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 32 में रखा गया था, जिसमें राज्य विधानसभाओं को सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी।

केंद्रीय नियंत्रण

- हाल ही के वर्षों में, केंद्र सरकार सहकारी समितियों पर अधिक नियंत्रण हासिल कर रही है।
- सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे में लाया गया है और हाल ही में, संघ ने एक केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है।
- सहकारिता विधेयक में संशोधन ने सहकारी समितियों के कामकाज में अधिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता के लिए सहकारी समितियों के विनियमन के लिए विभिन्न प्रावधान शामिल किए हैं।
- हालांकि, 2013 में, संशोधन विधेयक को गुजरात उच्च न्यायालय ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि यह राज्यों द्वारा अनुसमर्थित नहीं होने के कारण अनुच्छेद 368(2) के अंतर्गत आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा था और इस आधार पर भी कि 97वें संशोधन ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया है।

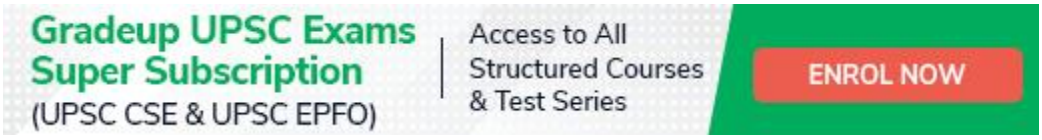

- गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, यह तर्क दिया गया था कि संशोधन ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की योजना को न तो प्रत्यक्ष और न ही प्रभावी रूप से बदला गया है, इसलिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की कोई आवश्यकता नहीं थी।
- उच्च न्यायालय में, संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि 97वें संशोधन द्वारा सम्मिलित किये गए भाग IXB ने राज्य विधानसभाओं पर उन क्षेत्रों में एक विशेष तरीके से कानून बनाने के लिए अनिवार्य दायित्व लगाया था, जिनमें उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए थी और यहां तक कि संशोधनों के कुछ खंड, कुछ मौजूदा राज्य विधानों को निरस्त करते हैं।
- उच्च न्यायालय ने तब पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संशोधन का हवाला दिया था।
- उन संशोधनों का राज्यों की विधायी शक्ति पर समान प्रभाव पड़ा था और राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन वाली विशेष प्रक्रिया द्वारा पारित किए गए थे।
- हालांकि, उच्च न्यायालय ने सिर्फ प्रक्रियात्मक कमी पर सवाल उठाया था, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले संशोधन की अनदेखी की गई थी।

विशिष्टता का निर्माण करना

- उच्च न्यायालय का निर्णय एक राज्य में संचालित सहकारी समितियों तक सीमित था, जिसमें बहु-राज्य सहकारी समितियों पर विचार नहीं किया गया था।
- हालांकि, कुछ लोगों की राय थी कि नए जोड़े गए हिस्से के प्रावधान, जो बहु-राज्य सहकारी समितियों से संबंधित हैं, सहकारी समितियों के लिए संबंधित भागों में स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं हो सकते हैं और इसलिए पूरे संशोधन को रद्द कर दिया जाना चाहिए।
- इस मामले में, संशोधन को केवल सही प्रक्रिया का पालन न करने के कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है लेकिन जिसके लिए केंद्र सरकार एक और संशोधन ला सकती है, जो राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की कठोरता से गुजरता है।
- राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के पास 28 राज्य विधानसभाओं में से 18 में बहुमत है, इसके अतिरिक्त, संशोधन को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन युग के दौरान पेश किया गया था, इसलिए यदि इसे फिर से पेश किया जाता है तो संशोधन के राजनीतिक विरोध की संभावना कम है।

एक सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र को अकेला छोड़ना

- सहकारी क्षेत्र हमेशा राज्यों या प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में रहा है।
- इन सहकारी समितियों के सिद्धांत और तंत्र एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होते हैं और उद्योग या फसल पर निर्भर करते हैं, जो सहकारी का आधार बनते हैं, लेकिन वे संशोधन जो एकरूपता लाने की कोशिश करते हैं, उसके परिणामस्वरूप गलत विकल्प और समाधान तैयार होते हैं।

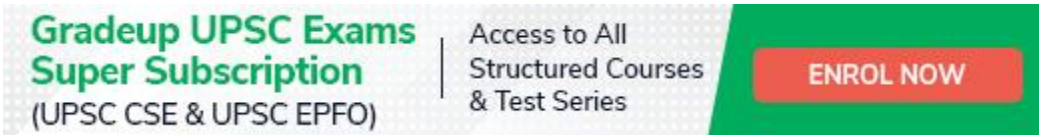

निष्कर्ष:

- ✓ सहकारिताओं पर नियंत्रण बढ़ने से कुछ राजनीतिक हित पैदा होंगे, जिनकी सहकारिता में अधिक रूचि होगी।
- ✓ सरकार को सही भावना से निर्णय लेना चाहिए और सहकारी क्षेत्र में उन्हें स्वतंत्रता और काम करने की स्वतंत्रता प्रदान करके हस्तक्षेप से दूर रहना चाहिए, जिससे कि वे सर्वोतम परिणाम दे सकें।
- ✓ इसके साथ ही, सहकारिता पर नए मंत्रालय के निर्माण पर दूसरा विचार किया जाना चाहिए।

स्रोत:

A judgment that must be taken in the right spirit:
https://thg.page.link/97EMLJ8EzzWMYKH16

संपादकीय लेख 2: जापानी शिक्षा समग्र विकास को सूचित करती है

टॉपिक: सामान्य अध्ययन पेपर 2 (न्यायपालिका)

संदर्भ:

- शिक्षा में निवेश से व्यक्तियों के लिए मजदूरी और समाज के लिए अच्छे नागरिक जैसे निजी और सामाजिक लाभ दोनों मिलते हैं।
- शोध के अनुसार, निजी लाभ शिक्षा के स्तर के साथ बढ़ते हैं लेकिन सामाजिक लाभ प्राथमिक स्तर पर चरम पर होता है।
- जब शिक्षित लोग कतार में लगने, वॉशरूम का उपयोग करने, हाथ धोना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना आदि जैसे नियमों का पालन करते हैं, तो ऐसे कार्यों से सामूहिक लाभ स्वच्छ, स्वस्थ और अनुशासित समाज जैसे सामाजिक मूल्यों को उत्पन्न करते है।
- हालिया महामारी ने हमें इस बात का पुनर्मूल्यांकन करने का अवसर दिया है कि हमारे स्कूलों को न केवल गणित, विज्ञान और भाषा में अकादमिक कौशल पर ध्यान केंद्रित करके बल्कि घर के कामों के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए समुदाय, प्रकृति और आदि से जुड़कर हमारी क्षमताओं का विस्तार करना चाहिए।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

शिक्षा में सुधार:

- हालिया वैश्विक महामारी ने लोगों को यह एहसास कराया है कि बहुत से लोग अपने घर के काम जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना आदि के लिए दूसरों के श्रम पर निर्भर हैं।
- इसके अतिरिक्त, जब आवश्यक आपूर्ति सीमित होती है और सार्वजनिक संसाधनों को बढ़ा दिया जाता है तो यह भारत में सामाजिक व्यवधान को बढ़ावा देता है।
- इससे निपटने के लिए हम जापान का उदाहरण ले सकते हैं और अपने प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से इस प्रकार की शिक्षा को विकसित कर सकते हैं।
- उदाहरण के लिए, 2011 में, जब जापान सुनामी की चपेट में आया था, तब भारी तबाही के बीच स्थानीय लोग धैर्यपूर्वक राशन के लिए कतार में खड़े दिखाई दे रहे थे। हाल ही में, कोरोनावायरस महामारी में भी, जापान में लोगों के जिम्मेदार व्यवहार के कारण स्कूल और सार्वजनिक स्थान उचित ढंग से खुले हुए हैं।
- भारत को जापानी प्रणाली से कुछ अंतर्दृष्टि सीखने की आवश्यकता है क्योंकि यह नई शिक्षा नीति को अपनाने के साथ अपने स्कूलों को फिर से खोलता है।

असंज्ञानात्मक तत्व

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (PISA) में जापान शीर्ष स्थान पर है, जो मुख्य शैक्षणिक विषयों में छात्रों के कौशल का मूल्यांकन करता है।
- हालांकि, शिक्षा के साथ-साथ जापानी पाठ्यक्रम गैर-संज्ञानात्मक तत्वों पर भी जोर देता है।
- जापान का शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEXT), जापानी स्कूली शिक्षा की परिभाषित विशेषताओं के रूप में 'ची-टोकू-ताई' पर ध्यान केंद्रित करता है।
- ची का अर्थ है 'जानना', जो मजबूत शैक्षणिक क्षमताओं के निर्माण पर जोर देता है।
- टोकू का अर्थ 'गुण' है और यह सावधानी, आत्म-अनुशासन और सहकारी क्षमताओं पर जोर देता है।
- ताई का अर्थ शरीर है और यह शारीरिक और मानसिक कल्याण को दर्शाता है।
- 1970 के दशक में जापानी शिक्षा में बड़े बदलाव हुए है, जहां इसने शिक्षा के एक अत्यंत परीक्षा-केंद्रित, रटने वाले संस्मरण-आधारित दृष्टिकोण से 'ची-टोकू-ताई' दृष्टिकोण में स्थानांतरण किया था।
- प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा, एकीकृत अध्ययन और विशेष गतिविधियों जैसे विषय शामिल थे, जो शैक्षणिक कौशल से परे समग्र क्षमता पर केंद्रित थे, जिसमें 'कांसेई' शामिल था, जो व्यापक रूप से अर्थ 'संवेदनशीलता' है।
- जापानी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य एक जानकार दिमाग विकसित करना है, जो सुंदरता और प्रकृति की सराहना कर सकता है, न्याय की भावना रख सकता है और जीवन और श्रम का सम्मान कर सकता है।

सामाजिक व्यवहार को आकार देना

- नैतिक शिक्षा में ऐसे मानदंड शामिल हैं, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार होने में मदद करते हैं और प्रकृति सहित सभी के प्रति विचारशील व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए, एक ग्रीष्मकालीन परियोजना के रूप में छात्र प्रकृति में भृंग, सिकाडा, क्रिकेट और स्केचिंग को देखते हुए या अपनी 'कीट डायरी' में उनकी विशेषताओं को नोट करते हुए उद्यम करते हैं।
- पहली कक्षा से, छात्र बारी-बारी से अपनी कक्षाओं, वाशरूम की सफाई करते हैं, स्कूल में दोपहर का भोजन परोसते हैं और स्कूल में पौधों को पानी देते हैं।
- जब छात्र चालक को प्रतीक्षा करवाते हुए पैदल यात्री क्रॉसिंग पार करते हैं तो वे आभार व्यक्त करने के लिए 'धन्यवाद' व्यक्त करते हुए झुकते हैं।
- उपरोक्त उदाहरणों से यह समझा जा सकता है कि प्राथमिक स्कूल पाठ्यक्रम, विनम्र और विचारशील समाज के निर्माण में एक जबरदस्त भूमिका निभा सकता है।
- जब छात्र विभिन्न कार्य करते हैं, तो इससे उनके भीतर कम उम्र में श्रम और विनम्रता के प्रति सम्मान पैदा करने में मदद मिलती है।
- यह छात्रों को अधिक जिम्मेदार बनाता है और समुदाय के प्रति विचारशील व्यवहार करने में मदद करता है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- उदाहरण के लिए, जापानी प्रशंसकों ने रूस में स्टेडियम में अपनी पंक्तियों को साफ करके कोलंबिया के खिलाफ 2018 फुटबॉल विश्व कप के उद्घाटन मैच में अपनी जीत का जश्न मनाया था।

निष्कर्ष निकालना

- शिक्षा पाठ्यक्रम को एकीकृत अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसमें अनुभवजन्य शिक्षा और स्वतंत्र सोच शामिल है, जहां छात्र अपने स्थानीय समुदायों में समस्याओं की पहचान करते हैं और समाधान के बारे में सोचते हैं।
- उदाहरण के लिए, छात्र अपने स्वयं के शोध के आधार पर आपदा तत्परता मानचित्र बना सकते हैं।
- वरिष्ठों द्वारा सामुदायिक इतिहास साझा किया जा सकता है, जो स्कूलों को समुदाय के साथ एकीकृत करने में मदद करेगा।
- बच्चों को उनके स्थानीय समुदायों में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों, प्रदूषण, अपशिष्ट निपटान आदि जैसी समस्याओं की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और समाधान रोड मैप विकसित करने में उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, इससे दोनों पक्षों को बहुत अधिक लाभ हो सकता है।
- विशेष गतिविधियों के घंटों में कार्यक्रम आयोजित करना, पुस्तकालय का रखरखाव करना आदि जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। कार्य पूरा होने के बाद, छात्रों को इस प्रक्रिया में अनुभव की गई समस्याओं जैसे कि अपव्यय, संघर्ष आदि का विश्लेषण करने के लिए कहा जाता है और फिर उन्हें हल करने के तरीके सुझाए जाते हैं, इससे 'कैज़ान'- निरंतर सुधार का जापानी दर्शनशास्त्र, के अभ्यास को विकसित करने में मदद मिलती है।
- जापानी समाज और शिक्षा प्रणाली 'सामूहिकतावाद' पर जोर देती है।
- पूंजीवादी पश्चिम के विपरीत, जापान एक सामूहिकतावादी समाज है।
- एक समूह के रूप में काम करना और समूह सद्भाव, जापानी समाज के लिए मौलिक है और वे इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि कोई व्यक्ति तभी जीतता है, जब समूह जीतता है, जो समान और एकजुट समाज बनाने में मदद करता है।

एकता के संदर्भ में

- उदाहरण के लिए, टोक्यो में तीसरी कक्षा के लिए एक खजाने की खोज गतिविधि आयोजित की गई थी, जिसमें टीमों को छिपे हुए खजाने को ढूंढना था लेकिन प्राथमिक लक्ष्य खजाना प्राप्त करना नहीं था बल्कि समूह को एकजुट रखना था।
- टीमें तभी आगे बढ़ सकती हैं, जब उसके सभी सदस्य एक साथ हों और अगली रणनीति पर सहमत हों। इसलिए, यदि छात्र व्हीलचेयर पर है या धीमी गति से चल रहा है तो समूह सम्मानपूर्वक उसके आने की प्रतीक्षा करता था।

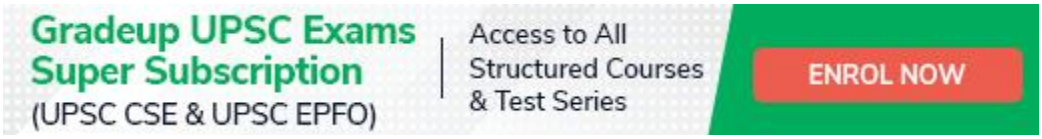

- अंतत: शिक्षकों को 'खजाना' प्रदर्शित करने और दर्शकों की तालियां बटोरने के लिए मंच पर जाने हेतु प्रत्येक समूह एक छात्र को चुनना था। हैरानी की बात है कि उन्होंने उस छात्र को चुना जो सामान्यत: इस संदर्भ में पीछे रहा था, जो प्रत्येक व्यक्ति शामिल किया हुआ और मूल्यवान महसूस कराता है।

निष्कर्ष:

- ✓ वैश्विक महामारी ने भारत को अपनी शिक्षा प्रणाली को फिर से तैयार करने का अवसर प्रदान किया है और जिसमें यह जापानी शिक्षा प्रणाली से बहुत सार्थक अंतर्दृष्टि प्राप्त सकता है और सामूहिकता की भावना के साथ बच्चों में नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी पैदा कर सकता है।

स्रोत:

Japanese education spells holistic development:
https://thg.page.link/ZAzMMNNQjnHKphw8A

gradeup

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW